>

Title: Need to provide jobs to the displaced persons by the Government Sector Companies in Jharkhand.

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): भारत सरकार के उपक्रमों सी.सी.एल., बी.सी.सी.एल, डी.बी.सी. एवं कोकारो स्टील प्लांट आदि जो झारखण्ड राज्य में स्थित है, इनके द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात् धरती पुत्र दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। न तो इन्हें नौकरी दी जा रही है और न ही इन्हें समुचित मुआवजा दिया जा रहा है। इससे संबंधित सरकार द्वारा विस्थापन-पूर्णकाल के नियम तो बने हैं परंतु इसका अनुपालन इन उपक्रमों द्वारा नहीं किया जा रहा है। जो न तो राज्य सरकार के हित में है और न ही इन उपक्रमों एवं विस्थापितों के हित में है। इस कारण से राज्य में इन्हीं उपक्रमों को अपने कार्य विस्तार के लिए या नए कल कारखाने लगाने में जनता का पारस्परिक सहयोग मिलना मुश्किल होता जा रहा है जिससे राज्य में उद्योग एवं रोजगार की संभावनाएं क्षीण होती जा रही है।

अतः मेरी मांग है कि उक्त उपक्रमों को जनहित में विस्थापन-पूर्णदर्शन के नियमानुसार कार्य करने हेतु संबद्ध विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।